



राँची/दिनांक 02.11.18

**विषय:-** नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या - 2135 दिनांक: 18.04.2016 द्वारा निर्गत "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" में संशोधन के सम्बन्ध में।

राज्य में बढ़ती जनसंख्या, जमीन तथा मकानों की कीमतों और मकान किराये में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं मुख्य रूप से कमज़ोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले आवासविहीन व मलिन तथा अनधिकृत बसितयों में निवासित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 2135 दिनांक: 18.04.2016 के द्वारा निर्गत की गयी है।

2. "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति-2016" में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

कंडिका संख्या	उप-कंडिका सं०	उप-कंडिका सं०	प्रावधान	संशोधित प्रावधान
5.5 Model 2: Development of Affordable Housing Projects	5.5.1 Affordable Housing Projects on PPP Model	5.5.1.1, Provision of Government Land	a) Affordable Housing area shall not be less than 65% of the total project area.	a) Affordable Housing area shall not be less than 55% of the total project area.
5.6 Model -3: In-situ Slum Redevelopment	5.6.1 Development on PPP Model	5.6.1.1 Mandatory Development Norms	(d) Number of Affordable Housing Units: Affordable Housing area shall not be less than 65% of the total project area. Bid documents shall specify the number of slum dwelling units to be built by the private developer for handing over to PDA. The construction specification along with the detailed plan of the Rehabilitation Area development shall also form part of bidding documents.	(d) Number of Affordable Housing Units: Affordable Housing area shall not be less than 55% of the total project area. Bid documents shall specify the number of slum dwelling units to be built by the private developer for handing over to PDA. The construction specification along with the detailed plan of the Rehabilitation Area development shall also form part of bidding documents.  The Developer Area will be given by PDA to private developer on freehold basis, as per the terms and conditions of the Concession Agreement.
5.12 Model 9 : Development of EWS/ LIG Housing on whole of Private Land		5.12.5	Mixed-use development in area reserved for EWS dwelling units: 5% of the built up area reserved for EWS units shall be developed as neighbourhood shopping and community facilities (if any). Out of same, 3% of the built up area shall be exclusively reserved for neighbourhood shopping facilities. The FAR consumed under this section shall form part of total built up area being developed for EWS housing. The provisions of Annexure - 5 shall also apply to these developments.	Mixed-use development in area reserved for EWS dwelling units: 5% of the built up area reserved for EWS units shall be developed as neighbourhood shopping and community facilities (if any). Out of same, 3% of the built up area shall be exclusively reserved for neighbourhood shopping facilities. The FAR consumed under this section shall form part of total built up area being developed for EWS housing.
5.12 Model 9 : Development of EWS/ LIG Housing on whole of Private Land		5.12.6 Other incentives and relaxations to developers	b) Fast track approval process: The projects under this model shall be eligible for fast track approval process as specified in Annexure - 5.	b) Fast track approval process: The projects under this model shall be eligible for fast track approval process as specified in Annexure - 4

कंडिका संख्या	उप-कंडिका सं०	उप-कंडिका सं०	प्रावधान	संशोधित प्रावधान
Annexure - 1	Annexure – 1: Norms regarding Unit Size, Cost of Construction & Sale Price	1. For Affordable Housing (AH) 2. Units	Criteria: Carpet Area (norm) Super Built-up Area	Criteria: Carpet Area
Annexure - 2: Principles and Mechanism of Allotment	2. Allotment of Affordable Housing (AH)	(A) Eligibility Criteria for Applicants	vi. The minimum lock-in period for transfer of ownership by the beneficiary will be 10 years from the date of handover of the unit.	vi. The minimum lock-in period for transfer of ownership by the beneficiary will be 15 years from the date of handover of the unit.

- मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या— 301 दिनांक: 11.03.2015 की कंडिका 1.1 के आलोक में उपरोक्त पर दिनांक: 30.10.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या—09 के रूप में रखीकृति प्रदान की गई है।
- यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा, तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

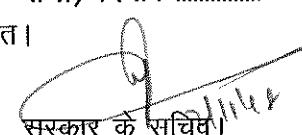
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

  
(अजय कुमार सिंह) ११/१८  
सरकार के सचिव।  
  
राँची/दिनांक: ०२.११.१८  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— 07 / विविध—नीति—05 / 2016 ५३८०

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची / नोडल पदाधिकारी, ई—गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रकाशनोपरांत संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

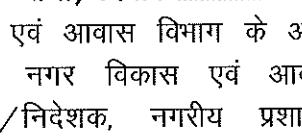
राँची/दिनांक: ०२.११.१८

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— 07 / विविध—नीति—05 / 2016 ५३८०

प्रतिलिपि:— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

राँची/दिनांक: ०२.११.१८

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— 07 / विविध—नीति—05 / 2016 ५३८०

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, जुड़को लिं०, राँची / निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय / संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड / परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुड़को लिं०, राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग / अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग / श्री कुणाल, विशेषज्ञ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

